



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2584]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2017/भाद्र 16, 1939

No. 2584]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2017/BHADRA 16, 1939

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2017

का.आ. 2946(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (जिसे इसमें इसके बाद मंत्रालय कहा गया है), भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को अनुदान, केंद्रीय क्षेत्र के अनुदान सहायता जिसे संस्थान के स्नातक, स्नातकोत्तर, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति और वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के विद्यार्थियों तथा अध्येताओं (जिन्हें इसमें इसके बाद लाभार्थी कहा गया है) को छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाता है।

और पूर्वोक्त स्कीमों में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं तथा सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थातः-

(1) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के ऐसे सभी विद्यार्थियों तथा अनुसंधान अध्येताओं, जो इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं, से यह अपेक्षित होगा कि वे आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार का अधिप्रमाणन करवाएं।

(2) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का ऐसा कोई भी विद्यार्थी या अनुसंधान अध्येता जो इन स्कीमों के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पात्र हैं परंतु उसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, उसे आधार नामांकन के लिए स्कीम में सम्मिलित होने के तीस दिनों के अंदर तक आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार पाने का हकदार हो; और ऐसे विद्यार्थी अथवा अनुसंधान अध्येता किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथोरिटी की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाकर आधार के लिए अपना नामांकन करवा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के नियम 12 के अनुसार, मंत्रालय भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है तथा यदि संबंधित जिला, ब्लॉक, ताल्लुक अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगी;

परन्तु आधार संख्यांक समानुदेशित किये जाने तक, किसी विद्यार्थी या अनुसंधान अध्येता उसे इन स्कीमों के अंतर्गत देय छात्रवृत्ति या अध्येतावृत्ति निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जा सकेगी, अर्थात:-

- (क) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा जारी छात्र पहचान पत्र; और
- (ख) (i) यदि छात्र या छात्रा ने नामांकन कराया है, तो उनके आधार नामांकन की पहचान पर्ची; या
- (ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए किए गए छात्र या छात्रा के अनुरोध की प्रति; और
- (ग) (i) बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या
- (ii) स्थायी खाता संख्यांक कार्ड या
- (iii) पासपोर्ट; या
- (iv) राशन कार्ड; या
- (v) मतदाता पहचान पत्र; या
- (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति, या
- (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी किसी व्यक्ति का फोटो सहित, पहचान पत्र; या
- (viii) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज।

परन्तु उक्त दस्तावेजों की भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन छात्रों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदा प्रदान करने के उद्देश्य से, मंत्रालय भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात:-

- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार करके आधार संख्यांक की अपेक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें यह सलाह दी जा सकेगी कि वे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में स्कीम में सम्मिलित होने के तीस दिनों के अंदर तक नामांकन करवाएं, यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं और स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) फायदाग्राहियों के आस-पास नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ होने की दशा में मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध

कराए और फायदाग्राहियों से अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य व्यौरों के साथ अपने नामों को पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य व्यौरों के साथ मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट संबंधित पदधारियों या कार्यान्वयन एजेंसी या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल पर अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होगी।

[फा.सं.।-12011/15/2016-आईएसआई]

अरुण कुमार यादव सयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(CENTRAL STATISTICS OFFICE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2017

S.O. 2946(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Statistics and Programme Implementation (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India gives grants to the Indian Statistical Institute (ISI), under its Central Sector Scheme of 'Grant-in-Aid to Indian Statistical Institute' to be used for providing stipends or fellowships (hereinafter collectively referred to as the benefit) to the students and fellows (hereinafter collectively referred to as beneficiaries) under its undergraduate, post-graduate, junior research fellowship and senior research fellowship programmes (hereinafter referred to as the Schemes);

And whereas, the aforesaid Schemes involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:

1. (1) All students and research scholars of the Indian Statistical Institute who are eligible to receive benefits under the Schemes are required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any student or research scholar of the Indian Statistical Institute who is eligible to receive benefits under the Schemes, but has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment within thirty days of his or her engagement under the scheme, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such student or research scholar may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through Indian Statistical Institute, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective District, Block, Taluka or Tehsil, the Ministry through Indian Statistical Institute shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to a student or research scholar, she or he shall be allowed to receive the stipend or fellowship due to her or him under the Schemes, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) Student identity card issued by the Indian Statistical Institute; and
- (b) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub paragraph (2) of paragraph 2; and
- (c) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with Photo; or
- (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

- (iii) Passport; or
- (iv) Ration Card; or
- (v) Voter Identity Card; or
- (vi) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
- (vii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or Tehsildar on official letter head; or
- (viii) any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the Indian Statistical Institute for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries under the Schemes, the Ministry through Indian Statistical Institute shall make all the required arrangements, including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the benefits under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas within thirty days of his or her engagement under the scheme, in case they are not yet enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, the Ministry through Indian Statistical Institute shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Indian Statistical Institute or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya, and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No. I-12011/15/2016-ISI]

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2017

का.आ. 2947(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्विघ्न रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) केन्द्रीय क्षेत्र की क्षमता विकास स्कीम के एक घटक के रूप में भारत सरकार के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर और शोधकर्ता छात्रों की प्रशिक्षुता स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है तथा मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों, भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों एवं विभिन्न राज्य सरकारों व सांख्यिकी निदेशालयों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है;

और, इस स्कीम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं (जिसे इसमें इसके बाद फायदाग्राही कहा गया है), सांख्यिकी, गणित सांख्यिकी, प्रचालन शोध, अर्थशास्त्र या जनांकिकी अथवा अनुप्रयोगिक सांख्यिकी क्षेत्र के स्नातकोत्तर और शोधकर्ता छात्रों को देश में सरकारी सांख्यिकी तथा संबंधित आंकड़ा संग्रहण, विधायन और विश्लेषण, प्रकाशन तथा प्रचार-प्रसार की प्रणाली से उन्हें परिचित कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षुता का अवसर दिया जाता है तथा साथ ही यह स्कीम सांख्यिकी के क्षेत्र में छात्रों को अपना व्यवसाय चुनने के बारे में सुग्राही बनाती है और भारत सरकार की भारतीय सांख्यिकीय सेवा और अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के बारे में उनमें जागरूकता पैदा करती है।

और, इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुता के सफलतापूर्वक पूरा होने पर छात्रों को मानदेय (जिसे इसमें इसके बाद फायदा कहा गया है) दिया जाता है, जिसके अंतर्गत भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अर्न्तवर्तित है;

केन्द्रीय सरकार अतः अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) ऐसे छात्र, जो इस योजना के अंतर्गत फायदा पाने के पात्र हैं, से यह अपेक्षित होगा कि वे आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या अधिप्रमाणन करवाए।
- (2) स्कीम में भाग लेने का इच्छुक कोई छात्र, जिनके पास आधार संख्यांक नहीं हो अथवा जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, को स्कीम में सम्मिलित होने के तीस दिनों के अंदर तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो तथा ऐसे छात्र आधार के लिए नामांकन करने हेतु किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूनिक पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जाकर आधार के लिए अपना नामांकन करवा सकेंगे।
- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के नियम 12 के अनुसार, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है तथा यदि संबंधित जिला, ब्लॉक, ताल्लुक अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगी; परन्तु व्यक्ति-विशेष को आधार संख्यांक समनुदेशित किए जाने तक, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन फायदा दिया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा छात्र या छात्रा को जारी छात्र पहचान पत्र; और
- (ख) (i) यदि छात्र या छात्रा ने नामांकन कराया है, तो उनके आधार नामांकन पहचान स्लिप; या
- (ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए किए गए छात्र या छात्रा के अनुरोध की प्रति; और
- (ग) (i) बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या
- (ii) स्थायी खाता संख्यांक कार्ड; या
- (iii) पासपोर्ट; या
- (iv) राशन कार्ड; या
- (v) मतदाता पहचान पत्र; या
- (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; अथवा
- (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी किसी व्यक्ति का फोटो सहित, पहचान पत्र; या
- (viii) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज।

परन्तु उक्त दस्तावेजों की केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन छात्रों का सुविधाजनक और निर्बाध फायदा प्रदान करने के उद्देश्य से, मंत्रालय सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात्:-

- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार करके आधार संख्यांक की अपेक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें यह सलाह दी जा सकेगी कि वे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में स्कीम में सम्मिलित होने के तीस दिनों के अंदर तक नामांकन करवाएं, यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं और स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।
 - (2) फायदाग्राहियों के आस-पास नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ होने की दशा में मंत्रालय, अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए तथा फायदाग्राहियों से अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य व्यौरों के साथ अपने नामों को पैरा 1 के उपपैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य व्यौरों के साथ मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट संबंधित पदधारियों या कार्यान्वयन एजेंसी या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल पर अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।
3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होगी।

[फा. सं. I-12011/15/2016-आईएसआई]

अरुण कुमार यादव, सयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2017

S.O. 2947(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Statistics and Programme Implementation (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering an Internship Scheme for Postgraduate and Research Students of the recognised Universities in India (hereinafter referred to as the Scheme) as one of the components of the Central Sector Scheme of Capacity Development, and implemented through various Offices under the Ministry, various Departments and Ministries of the Government of India and the Directorate of Economics and Statistics of the various State Governments (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, under the Scheme, Post-graduate or Research Students of Statistics, Mathematical Statistics, Operational Research, Economics or Demography or any of the applied field of Statistics of recognised Universities or Institutions (hereinafter referred to as the beneficiaries) are given the opportunity for internship with an objective of familiarising them with the prevailing system of Official Statistics in the country and related data collection, processing and analysis, publication and dissemination and the Scheme also sensitises the students about choosing their career in the field of Statistics and creates awareness amongst the students about Indian Statistical Service and the Sub-ordinate Statistical Service of the Government of India;

And whereas, under the Scheme, honorarium is paid to the students on successful completion of the internship (hereinafter referred to as the benefit), which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Statistics and Programme Implementation hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Any student eligible for availing benefit under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any student desirous of participating in the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment within thirty days of his or her engagement under the scheme, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such student may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective District, Block, Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI :

Provided that till the time Aadhaar number is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) Student identity card issued to her or him by the University or Institution; and
- (b) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (c) (i) Bank Passbook or Post Office Passbook with photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(vii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or Tehsildar on official letter head; or
(viii) any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the Central Government for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefit to the students under the Scheme, the Ministry shall make all the required arrangements including the following, namely:-
- (1) wide publicity through media and website of the Ministry shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the benefit under the Scheme and the beneficiaries may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas within thirty days of his or her engagement under the scheme in case they are not yet enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.
- (2) in case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries shall be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as

specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No. I-12011/15/2016-ISI]

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.